(ii) Tenancy reforms have led to conferment of ownership rights or to protection against eviction to 112.13 lakh cultivators in respect of about 153.32 lakh acres of land.

(iii) Under the ceiling programme, 73.51 lakh acres of land have been declared surplus of which 50.58 lakh acres have been distributed to 48.88 lakh beneficiaries mostly belonging to the weaker sections.

(iv) Most states have enacted legislations for consolidation of holdings either on compulsory or on voluntary basis leading to consolidation of 1528.76 lakh acres of land.

(v) Surveys for updating of land records are being done in a number of States.

(vi) Computerisation of land records projects have been taken up to enable the land holders to get an updated copy of their record of rights quickly and at a cheaper rate. In all 60 Projects are in various stages of implementation.

(vii) Land reforms is a multi-facet programme. States have achieved different levels f success in different programmes.

2. It is not possible to fix the targets for various land reform programmes. However, annual targets for distribution of ceiling surplus land are fixed under point no. 5 of Twenty point Programme. The targets for the last year 1993-94 were fixed at 598563 acres. The achievements reported were at 70887 acres.

). The Government of India periodically reviews implementation of land reforms in the States. In the Conference of Revenue Ministers of States held in March, 1992 at New Delhi, the States have undertaken to speed up distribution of ceiling surplus land.

**नलकूप लगाने हेतु ड्रिलिंग उपकरणों के लिए धनराशि**

*273. **श्री कैलाश नारायण सारंग** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मध्य प्रदेश ने राज्य को धसकने वाली भूमि में नलकूप लगाने के लिये ड्रिलिंग करने और पठारी क्षेत्रों में गहराई तक ड्रिलिंग करने हेतु हाई प्रेशर डीप ड्रिलिंग काम्बिनेशन रिंग और हाइड्रोफ्रेक्चरिंग मशीनें खरीदने के लिये धनराशि की मांग की है ;

(ख) यदि हां, तो भारत सरकार द्वारा उक्त प्रस्ताव को अब तक स्वीकृति न दिये जाने के क्या कारण हैं ; और

(ग) सरकार द्वारा इस प्रस्ताव को कब तक स्वीकृति दे दिये जाने की संभावना है ?

**ग्रामीण विकास मंत्रालय (ग्रामीण विकास विभाग) में राज्य मंत्री (श्री उत्तम भाई पटेल)** : **नलकूप लगाने हेत ड्रिलिंग (उपकरणों के लिए धनराशि** (क) से (ग) मध्यप्रदेश सरकार से 470.30 लाख रुपये की अनुमानित लागत पर 1161 डीप ड्रिलिंग कम्बीनेशन रिग्स तथा दो हाइड्रोफ्रेक्चरिंग यूनिटों की खरीद के लिये एक प्रस्ताव सितम्बर, 1993 में प्राप्त हुआ था। राज्य सरकार ने कहा था कि यह 100 लाख रुपये अपनी निधियों से जुटायेगी तथा उन्होंने शेष राशि के लिये केन्द्रीय सहायता मांगी थी । प्रस्ताव को तकनीकी पहलुओं से जांच की गई थी और नवम्बर, 1993 में राज्य सरकार से विद्यमान रिगो/हाइड्रोफ्रैक्चरिंग यूनिटों, आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ड्रिल किये जाने वाले कुल नलकूपों, संभावित हाइड्रोफ्रैक्चर किये जाने वाले नलकूपों के ब्यौरे और कुछ अन्य तकनीकी स्पष्टीकरण मांगे गये थे । राज्य सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है । पूरे ब्यौरों के साथ प्रस्ताव प्राप्त होने पर इसे स्वीकृत करने हेतु केन्द्रीय भू-जल बोर्ड से परामर्श करके इसकी जांच की जायेगी ।